अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोग एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और हैलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, वहीं महत्वपूर्ण है कि एक दक्षता हम अपने सर्विस स्टैण्डर्ड के आधार पर अपनी संस्थाओं में भी लाएं। मेरे कई सहभागियों ने डीजीसीए के बारे में चर्चा की थी। प्रधान मंत्री जी की विचारधारा है कि दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमने डीजीसीए को ईजीसीए में परिवर्तित किया है। डीजीसीए की 298 सेवाएं, जो हैण्ड रिटिन होती थीं, वह अब इलैक्ट्रोनिक फॉर्मेट में हो चुकी हैं। मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। पायलट्स, एएमईज़ और एटीसीओज़ के लिए, यहां पर कल एटीसीओज़ की भी चर्चा की गई थी, पहले उनके लाइसेंस कागज पर बनाए गए, लेकिन अब न्यू स्मार्ट कार्ड लाइसेंस बनेंगे, जो क्यू आर कोड और स्कैनिंग के आधार पर ईजीसीए पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। पायलट के मेडिकल एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड लिखने के लिए डॉक्टर के पास जाने में करीब-करीब 20 से 30 दिन लगते थे। अब ई-फॉर्मेट के अंदर दो या चार दिन में पायलट का मेडिकल एग्जामिनेशन संभव हो पाएगा। उसी तरह से अनेक विषयों में भी इसके आधार पर हम लोग वृद्धि ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और नई सोच सदन के पटल पर रखना चाहता हूं और वह डिजी यात्रा है। वर्तमान में कई बार एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइनें होती हैं। पहले बाहर सीआरपीएफ चैक करती है, फिर अंदर बैगेज काउंटर पर चैकिंग होती है और उसके बाद सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। हमने डिजी यात्रा एक नई योजना निकाली है, जहां फोन डिब्बे के आधार पर आपका आधार कार्ड और आपके चेहरे के साथ मैचिंग किया जाएगा तथा बायोमैट्रिक के आधार पर वह बोर्डिंग पास के साथ सीमलेस्ली सिंक्रोनाइज किया जाएगा। विमान तल पर आपका अनुभव एक सीमलैस अनुभव होगा। खाली काउंटर्स लगाए जाएंगे, आप टिकट को स्कैन करेंगे, काउंटर खोलकर आपको आवागमन के लिए सुविधा दी जाएगी। हम लोगों ने इसके पहले फेज में सात एयरपोर्ट्स निर्धारित किए हैं और हम इनको एक-एक करके करेंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के अंतर्गत पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, वाराणसी और निजी एयरपोर्ट्स के अंतर्गत दिल्ली, बेंगलुरु तथा हैदराबाद का एयरपोर्ट है। यह कई देशों में संचालित किया गया है, उनमें चाहे दुबई हो, अटलांटा हो, टोक्यो हो, लंदन हो, सिंगापुर हो या एम्सटर्डम हो। इससे करीब 30 से 40 प्रतिशत वेट टाइम में कमी पाई गई है, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिली है। कल हमारे नागर विमानन क्षेत्र के वित्तीय संकट के बारे में बहुत चर्चा की गई है।

(1305/RAJ/SM)

यह जरूर सत्य है कि कठिन परिस्थिति से यह क्षेत्र जुड़ा है। कई माननीय सांसदों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से जिस दिन में मैंने इस विभाग का प्रभार संभाला है, मेरी विचाराधारा यही थी कि इस क्षेत्र के जो पिन प्वाइंट्स है, हमें पिन पॉइंट्स को रिजॉल्व करना है। मैं मानता हूं कि अगर यह विचार-विमर्श के आधार पर होगा, तो ज्यादा एक रिच डायलॉग होगा। उसी के आधार पर एक युद्ध स्तर पर जो प्रदेशों के द्वारा एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट मुहैया किया जाता है, यह कई राज्यों में एक से पांच प्रतिशत तक सीमित है। जुलाई, पिछले वर्ष जिस दिन मैंने प्रभार संभाला, हमारे देश के 36 राज्यों और यूनियन

टेरिटरीज के बीच में 12 राज्य ऐसे थे, जो एक आधुनिक दूर-दृष्टिकोण की विचारधारा रखते थे, जिन्होंने अपना वैट एक प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक सीमिति कर दिया। पर, 24 राज्य ऐसे थे, जहां एटीफ पर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक वैट था, अब आप यह समझिए कि जिस इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर एयर टर्बाइन फ्यूल 40 प्रतिशत है, अगर उस पर 20 से 30 प्रतिशत का भार हो, तो वह इंडस्ट्री किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी। मैंने एक-एक राज्य के माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन किया है और मैं इस सदन के पटल पर उन राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने शीघ्र कैबिनेट मीटिंग की, कैबिनेट ऑर्डर पास किया, गजट नोटिफिकेशन किया। मैं उल्लेख भी करना चाहता हूं कि यूनियन टेरिटरीज और राज्यों को मिला कर 12 राज्यों ने अपनी वैट की लेवल को 20-30 प्रतिशत से घटा कर एक से चार प्रतिशत तक सीमित कर दिया। मैं उन राज्यों का उल्लेख करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप एक्साइज के बारे में बताइए।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, कई अनुभवों में यही विचारधारा होती है कि अच्छा भी है तो विरोध करो और बुरा भी है, तो विरोध करो और हम उसे छाती पर लेने के लिए तैयार हैं।

अंडमान और निकोबार, यूनियन टेरिटरी में 10 प्रतिशत वैट लगता था, वहां के संचालक ने एक प्रतिशत तक सीमित कर दिया। त्रिपुरा राज्य में 15 प्रतिशत वैट लगता था, त्रिपुरा ने वैट एक प्रतिशत तक सीमित कर दिया। हरियाणा में 20 प्रतिशत वैट लगता था, उसने वैट एक प्रतिशत तक सीमित किया। उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत वैट लगता था, लेकिन आज वहां एक प्रतिशत वैट है। लद्दाख में 26 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां एक प्रतिशत वैट है। जम्मू-कश्मीर में 26 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां एक प्रतिशत वैट है। उत्तराखंड में 20 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां वैट दो प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में 25 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां वैट दो प्रतिशत है। मध्यम प्रदेश में 25 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां वैट चार प्रतिशत है। गुजरात में 30 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां वैट चार प्रतिशत है। कर्नाटक, जहां बेंगलुरु एयरपोर्ट स्थापित है, सबसे बड़ा मेट्रो एयरपोर्ट स्थापित है, वहां 28 प्रतिशत वैट लगता था, आज वहां वैट केवल 18 प्रतिशत है। मैं इन 12 राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों और संचालकों को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं इसका लाभ भी समझा दूं, क्योंकि कोई भी कदम अगर कोई उठाए तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए। आंध्रप्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 साल पहले इस वैट को घटा कर रखा था, तीन महीने के अंदर आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में 15 प्रतिशत फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ गई और उसी के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर ने अभी एक प्रतिशत वैट लगाया, दो हफ्ते के अंदर जम्मू-कश्मीर में रिफ्यूलिंग में 360 प्रतिशत वृद्धि हुई है, क्योंकि प्लेन्स वहीं रिफ्यूल करेंगे, जहां ईंधन सस्ता हो। मैं यही समझाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, खास कर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य, जहां वैट 25 प्रतिशत और 29 प्रतिशत है, कृपा करके आप इस योजना से जुड़ें ताकि हम लोग आपके राज्य में भी ज्यादा एयरपोर्ट्स और आवागमन की सुविधा बढ़ा पाएं।

(1310/VB/KSP)

मैं सांसदों से निवेदन करूँगा कि जो 12 राज्य बचे हैं, जो 12 और 24 का रेशियो था, वह अब 24 और 12 हो गया है। इसलिए जो 12 राज्य बचे हैं, आप मेरी मदद कीजिए ताकि आपके राज्य में भी हम आवागमन की सुविधा बढ़ा पाएं।

वैट के साथ-साथ, हमारी विचारधारा है कि सिविल एविएशन केवल एयरपोर्ट्स और प्लेन्स तक ही सीमित नहीं है। हमें एक पूरा इको-सिस्टम निर्धारित करना होगा। सिविल की इको-सिस्टम में कार्गो महत्वपूर्ण है, एमआरओ महत्वपूर्ण है और एफटीओज यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस महत्वपूर्ण हैं। कल की चर्चा में इनका कई बार उल्लेख हुआ था। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ कि कार्गो के क्षेत्र में हमारी बहुत क्षमताएं हैं। लेकिन भारत में हमें उन क्षमताओं को खोलना होगा। पिछले एक वर्ष में, सदन के पटल पर यह रखते हुए मुझे खुशी है कि इंटरनैशनल फ्रेट के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का मार्केट शेयर, जो केवल दो प्रतिशत तक सीमित था, कोविड के वातावरण में, आज 19 प्रतिशत हो गया है। कार्गो का रेवेन्यू, जो केवल 15 सौ करोड़ रुपए था, वह आज 23 सौ करोड़ रुपए हो चुका है और 150 नए पैसेंजर प्लेन्स भी कार्गो में परिवर्तित हो चुके हैं।

इसमें सरकार की क्या भूमिका है? इसमें हमारी यही भूमिका है कि हम लोग कार्गो टर्मिनल्स बनाएं। कल माननीय हेमामालिनी जी ने भी निवेदन किया था कि हमें एयर फ्रेट स्टेशंस को भी विकसित करना होगा। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो ए-क्लास कम्पनियाँ हैं, उनके आधार पर हमारे 21 इंटरनैशनल कार्गो टर्मिनल्स हैं, 33 डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स हैं, दो कुरियर के कार्गो टर्मिनल्स हैं। पिछले दो वर्षों में, कोविड के वातावरण में, हमने 16 अतिरिक्त पैसेंजर टर्मिनल्स कार्गो के लिए विकसित किए हैं और आने वाले तीन वर्षों में हम 33 नए डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स बनाने जा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को भी हम लोग विकसित कर पाएं।

कार्गो के साथ-साथ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमें एक नई ऊर्जा लानी होगी। वर्तमान में देश में 34 एफटीओज हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए 229 एयर-क्राफ्ट्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में, कोविड काल में भी लगभग 862 नए कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यू किए गए हैं, जिनमें से 504 भारतीय एफटीओज के द्वारा किए गए हैं, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है। आने वाले एक वर्ष में नौ नए एफटीओज स्थापित होने जा रहे हैं। ये एफटीओज बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी (असम) में होंगे। दूसरे फेज के रूप में, हमने 15 नए एफटीओज और 10 नए एयरपोर्ट्स के लिए टेंडर प्रॉसेस की शुरुआत की है। इसमें कूचबिहार, तेजू, झारसुगड़ा, देवघर, मेरठ, किशनगढ़, हुबली, कडप्पा, भावनगर और सेलम शामिल हैं। इन सभी स्थानों में एक-एक नया एफटीओ देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं।

हमारी विचारधारा है कि नई तकनीक के आधार पर हम लोग नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आएं। प्रधानमंत्री की विचारधारा है कि हमें ऐसे क्षेत्रों में अपना ध्यान आकर्षित करना होगा, जहाँ भारत एक फॉलोअर न हो, बल्कि एक ग्लोबल लीडर हो। ड्रोन क्षेत्र, जिसका उल्लेख कल श्री गडकरी साहब अपने उद्बोधन में कर रहे थे, यह एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिसमें भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।

हमने एक वर्ष में नए रूल्स स्थापित किए, 120 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम लेकर आए हैं, एक नया एयर स्पेस मैप लेकर आए हैं। हमारा विश्वास है कि अनेक मंत्रालयों के साथ मिलकर ड्रोन को पूरे देश के कोने-कोने और गांव-गांव तक हम प्रचलित करें। ड्रोन टेक्नोलॉजी की यह क्षमता है कि लगभग 10 हजार डायरेक्ट जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में और लगभग पाँच लाख रोजगार के अवसर हम लोग ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री में अर्पित कर पाएंगे। इसी विचारधारा के साथ इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम आगे ले जा रहे हैं।

नागर विमानन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जरूर है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो विवरण देने की कोशिश की है, उससे इस क्षेत्र का महत्व, इस क्षेत्र का भारत के प्रति योगदान, जिसका उल्लेख मैंने करने की कोशिश की है, उसकी जो विचारधारा थी कि मंत्रालय क्या करता है, शायद इसके बारे में जितनी भी कठिनाइयाँ हों या मस्तिष्क में गलतफहमियाँ हों, मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के आधार पर वे दोबारा नहीं उभरेंगी।

(1315/PC/KKD)

हमारा कर्तव्य है कि प्रधान सेवक के नेतृत्व में जन-सेवक के रूप में हम लोग कार्य करें और वही विचार इस नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं, जो प्रश्न सांसदों ने उठाए थे। पहला प्रश्न शर्मिष्ठा सेठी जी का था, बाकी प्रश्नों के उत्तर मैं जवाब के आधार पर जरूर भेजूंगा। उनका प्रश्न था कि डीजीसीए और बीसीएएस के बजट में कटौती की गई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजट एस्टिमेट के आधार पर रेवेन्यू के हेड पर डीजीसीए के लिए 16 प्रतिशत की वृद्धि इस साल के बजट में की गई है, जो 180 करोड़ रुपये से 208 करोड़ रुपये की गई है। बीसीएएस का 44 करोड़ रुपये से करीब-करीब 70 करोड़ रुपये किया गया है, 55 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। कई माननीय सदस्यों ने एटीसीओज की शॉर्टेज का मुद्दा उठाया था। रवनीत जी, महुआ जी, रूडी साहब, श्रीकंदन जी, हनुमान बेनीवाल जी और अधीर दा ने यह मुद्दा उठाया था। इस क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। पिछले साल 67 नए एयरपोर्ट्स बने हैं। उसके आधार पर सैंकशन्ड पोस्ट्स 3,871 हैं, वर्तमान में 3,163 पोस्ट्स भरी हुई हैं और 708 पोस्ट्स खाली हैं। मैं सदन के पटल पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि करीब-करीब 350 पोस्ट्स अगले छ: से दस महीनों के अंदर भरी जाएंगी।

इसी के साथ-साथ जो 361 पोस्ट्स हैं, वे अगले तीन महीनों के अंदर भरी जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमने यह प्रस्ताव मूव किया है कि 340 अतिरिक्त एटीसीओज का सैंक्शन हमें वित्त मंत्रालय से मिले, ताकि हम लोग इसका संचालन अच्छे से कर पाएं। अनेक एयरपोर्ट्स की चर्चा की गई थी। बिट्टू साहब और अमर सिंह जी ने कहा था कि हलवारा एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। यह Airports Authority of India और पंजाब सरकार के बीच का 51:49 का जॉइंट वेंचर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मार्च, 2023 तक यह एयरपोर्ट तैयार होकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी के साथ बिट्टू जी ने कहा था कि विमान तल पर लोकल संस्कृति और कला का एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए।

यही हमने अगरतला, देहरादून और कुशीनगर के एयरपोर्ट पर दिखाया है। हम नहीं चाहते कि हमारे एयरपोर्ट्स विदेश के एयरपोर्ट्स के साथ बनें, ये भारत के एयरपोर्ट्स हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, भारतीय इतिहास का संचालन और क्षेत्रीय इतिहास का संचालन होना चाहिए। यह नियम मैंने पहले ही दिन बना दिया था।

इसी के साथ महुआ जी ने बागडोगरा और श्रीनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्रश्न उठाया था। बागडोगरा एयरपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जमीन एआईआई को दी है। हम जल्द से जल्द इसके कार्य की शुरूआत करेंगे। श्रीनगर के लिए एक हजार करोड़ रुपये की नई टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है। इसका डीपीआर भी पास हो चुका है और जल्द से जल्द कार्य शुरू होगा। इसी के साथ आपने लेह एयरपोर्ट की भी बात की थी, वहां केपैसिटी एक्सपैंशन चल रहा है और अगस्त, 2023 तक यह क्षेत्र की जनता को समर्पित हो जाएगा।

संतोष कुमार जी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का विषय उठाया था। नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जब भारतीय वायु सेना हमें जमीन देगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दो सालों के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार करके हम आपको समर्पित करेंगे। चेन्नई के लिए द्वितीय एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया गया था। वहां तमिलनाडु सरकार के द्वारा चार साइट्स सजेस्ट की गई थीं। हमने दो साइट्स स्वीकृत की हैं, उनकी स्वीकृति का पत्र भी हमने आपकी सरकार को भेजा है। जल्द से जल्द जवाब आए कि कौन सी साइट वे चूज़ करना चाहते हैं, जिसके बाद हम लोग चेन्नई में सेकेंड एयरपोर्ट की शुरूआत करने के लिए तैयार हैं।

शर्मिष्ठा जी ने पुरी के एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया था। पुरी एयरपोर्ट के लिए हमने फिजिबिलेटी रिपोर्ट ओडिशा सरकार को दे दी है। उनके निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास उनका निर्णय आने के बाद हम लोग तीव्र गति से उसको तैयार करेंगे। डकोटा की शिफ्टिंग के बारे में कहा था, बीजू पटनायक साहब का विषय था। कोई भी परमिशन अगर एयरपोर्ट एथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी जानी है, तो उसे हम लोग जल्द से दिलवाएंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। श्रावस्ती एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया गया था। यह कोड-बी एयरपोर्ट भी 19 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए तैयार है। इसकी लाइसेंसिंग की प्रकिया जारी है और इसकी शुरूआत भी हम जल्द से जल्द करेंगे।

(1320/IND/RP)

माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में कोटा एयरपोर्ट के लिए भी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जमीन मिलते ही उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा, इसका विश्वास मैं अध्यक्ष जी को दिलाता हूं। कलबुरगि एयरपोर्ट के लिए नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी का उमेश जाधव जी ने प्रश्न उठाया था।... (व्यवधान) झालावाड़ के एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत हम सम्मिलित करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी कलबुरगि में है। कोलकाता के एयरपोर्ट के बारे में अधीर दा ने प्रश्न उठाया था और सुदीप दा ने भी पिछले प्रश्न काल में मुझे निवेदन किया था। मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर कम से कम आप दोनों एक हो जाएं। सुदीप जी का प्रस्ताव आया है कि हम दुर्गापुर में एयरपोर्ट बनाएं।

दुर्गापुर 150 किलोमीटर दूर है। क्या आप कोलकाता के वासियों को 150 किलोमीटर दूर विमान तल में पहुंचने के लिए भेजना चाहते हैं? आप दोनों कृपया एक साइट तय कर लीजिए, हम वहां आप दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कालीकट एयरपोर्ट के बारे में है। आप सभी को मालूम है कि वहां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी। हमारे मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए और सुरक्षा के साथ हम कोई शार्टकट नहीं कर सकते हैं। पूर्व वायु सेना अध्यक्ष फली नरीमन जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की गई। वह रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस रन वे को हमें एक्सटेंड करना होगा, वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट प्रचलित करना होगा और कोडसी एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है। मैं सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि आप मेरी मदद करें। सरकार से हमें साढ़े 18 एकड़ लैवलाइज्ड जमीन की जरूरत है, क्योंकि वहां खाई है। वह जमीन मिलते ही उस एयरपोर्ट का तीव्र गति से हम रन वे का एक्सपेंशन करेंगे और फिर वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट की शुरूआत करेंगे। नवनीत जी ने पूछा था कि अमरावती एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन किए हैं और यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलते ही जितनी भी राशि की जरूरत है, हम देंगे ताकि अमरावती एयरपोर्ट की शुरूआत हम कर पाएं। पुडुचेरी के लिए वैथिलिंगम जी ने बेंगलुरु और हैदराबाद की कनेक्टिविटी के लिए प्रश्न उठाया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि 27 तारीख को दोनों शहरों से कनेक्टिविटी यथावत शुरू की जाएगी, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मेरे भाई श्रीकृष्णा देवरायालू जी ने आंध्र प्रदेश की कनेक्टिविटी का प्रश्न उठाया था। समर शेड्यूल में हम विजयवाड़ा को कड़प्पा के साथ जोड़ रहे हैं और तिरुपति को शिरडी और त्रिची के साथ जोड़ रहे हैं। मुरादाबाद के बारे में हसन साहब ने प्रश्न पूछा था। मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि 23 करोड़ रुपये हमने उस एयरपोर्ट के लिए आबंटित किए हैं। वह डेवलप हो चुका है और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू है। वह खत्म होते ही कानपुर-मुरादाबाद और लखनऊ-मुरादाबाद दोनों की कनेक्टिविटी हम शुरू करेंगे। इसी के साथ पाइंट ऑफ काल और जॉब लासेस की भी चर्चा हुई थी। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द दोनों विषयों पर कार्य करें।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। दो नई एयरलाइन्स की शुरूआत आने वाले वर्ष में इस क्षेत्र में... (व्यवधान) मैं आपको समय दे दूंगा, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप किसी भी सदस्य को आश्वासन मत दे दिया कीजिए कि मैं समय दे दूंगा। समय तो मुझे देना है कि किस-किस सदस्य को बोलने का मौका देना है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महोदय, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कहा कि 'मुझे समय दे दीजिए।' दो नई एयरलाइन्स जेट और अकासा की शुरूआत हो रही है, जो पिछले बीस सालों से सारी एयरलाइन्स बंद हो गई थीं। हमारी आशा अभिलाषा बहुत ऊंची है। सफर आसान नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा फोकस लक्ष्य पर है, क्रियान्वयन क्षमता पर है और मैं यही मानता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास तथा आप सभी के आशीर्वाद से हम इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।... (व्यवधान) (इति)

(1325/NKL/KDS)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। नागर विमानन मंत्रालय संबंधित अनुदान मांग पर 4 घंटे चर्चा के स्थान पर 8 घंटे 10 मिनट तक चर्चा हुई है। 59 माननीय सदस्यों ने इस पर बोला है और 36 माननीय सदस्यों ने अपने भाषण को 'लेड' किया है। मुझे लगता है कि इस पर लगभग 200 प्रतिशत चर्चा हो चुकी है। श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी, आपको मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, अत: आप कृपया अपनी बात रखें।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I feel that Shri Jyotiraditya Scindia is very articulate. I appreciate his performance and his style of reply. But I am surprised to see that the Tata Group has taken lease against Rs. 18000 crore, which has not been mentioned in the Budget Speech. Why has it not been mentioned?

Sir, when we board the aircraft, Shri Ratan Tata's voice message of 25 seconds is floated amongst the passengers in which he asks for the cooperation of all the persons. I would like to tell one thing. There may be a feeling that I am talking against Shri Ratan Tata. It is not so. We are in favour. Air India has been leased out to Shri Ratan Tata. I support it. Shrimati Mamata Banerjee has supported it but with one or two conditions. Please see that nobody loses his job. किसी को नौकरी से मत हटाइए। हमारे बंगाल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर आप राज्य सरकार को, मुझको और अधीर रंजन चौधरी जी को हाथ जोड़कर अपनी ड्यूटी छोड़ देने का काम मत करिए। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी को आपकी बीजेपी पार्टी ने भी बहुत ऊपर उठाने का काम किया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वह हमारे बंगाल से हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर आप कुछ तो करिए। सारे देशवासी आपका अभिवादन करेंगे। हमारे बंगाल में छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स- चाहे मालदा हो, चाहे कूच बिहार आदि हों, इनके लिए भी आप थोड़ा अलॉटमेंट कीजिए।

Sir, according to my long experience of 50 years in politics, my feeling is that the eastern region of India is the worst sufferer of regional imbalances after Independence. चाहे बंगाल हो, बिहार, असम, ओडिशा या त्रिपुरा हो, देश के इतने राज्यों के बारे में यहां चर्चा हो गई, लेकिन बंगाल के बारे में चर्चा यह हुई कि मैं और अधीर एक साथ हो जाएं और उनके लिए कुछ जमीन निकाल दी जाए।

I was not waiting for this Budget. I want to hear from Shri Jyotiraditya Scindia what the settlement was, and how Shri Ratan Tata agreed to take on the lease. How much money did this Government have to pay to clear their dues? After clearances of dues of more than Rs. 91,000 crore, Shri Ratan Tata agreed to take it up. I appreciate Shri Ratan Tata's attitude. Let him carry on the airways in a bigger way. We are in support. But the Government must not hide the truth. This is my request to Shri Jyotiraditya Scindia.

माननीय अध्यक्ष : श्री एनके प्रेमचनद्रन जी, कृपया एक मिनट बोलें। इस पर दोबारा चर्चा नहीं होगी।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Demands for Grants under the control of the Ministry of Civil Aviation are being discussed here after privatising Air India. I fully appreciate the articulation of our learned friend, Shri Jyotiraditya Scindia. But the focal point to be discussed and responded was regarding the privatisation of Air India. Nothing is mentioned about it. It is quite unfortunate.

Sir, I have raised so many issues regarding the Air India employees. The employees who are entitled to be in service up to the age of 58 years, have to retire as soon as the Tata took over. So, what is the fate of those retired employees of Air India.

As far as the medical benefits are concerned, they are entitled to avail these benefits even after retirement. So, I would like to ask whether these medical benefits and all other welfare schemes will be applicable to the Air India employees. These are the pertinent questions which we have put. Unfortunately, nothing has been answered. So kindly respond to these questions also.

(1330/MMN/CS)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, yesterday I had raised the issue of airfares concerning the Middle-East passengers. In the peak season, the airline companies are raising the airfares in a big way. So, the common passengers are not able to afford it, especially, the Middle-East passengers. The hon. Minister did not reply to this issue.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I thank the Minister for clarifying that the airports are only being leased out, and not disinvested. The State Governments have given land to the Airports Authority for free. So, when you are leasing it out, what happens to the share of the State Government? I just want a clarification on this.… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा है कि एक विषय पर 8 घंटे चर्चा हुई है। अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन लेना है तो आप मंत्री जी से बाद में ले लेना।

… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महोदय, हमारे सांसदों ने और हमारे वरिष्ठ सांसदों ने जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वह एयर इंडिया का मुद्दा है।… (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सर, जिन माननीय सदस्यों का भाषण ले हुआ है, कृपया उनका भी जवाब दे दीजिएगा।... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : जो अभी मुद्दे उठे हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे सुदीप दा ने कहा, प्रेमचन्द्रन जी ने कहा और इसे सदन के पटल पर भी मैं रखना चाहता था। मैं घड़ी देख रहा था कि लंबा समय हो रहा है, लेकिन जरूर इस पर विस्तृत तरीके से मैं अपने पॉइंट्स को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।... (व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करूँ।

महोदय, एयर इंडिया देश का नवरत्न था। निजी क्षेत्र से इसकी शुरूआत हुई, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई साल इसे सफलतापूर्वक चलाया गया था। जो आज एयर इंडिया की स्थिति हुई है, जो सुदीप दा ने वर्णन किया और प्रेमचन्द्रन जी ने बड़े विस्तृत तरीके से अपनी चर्चा में और कट मोशंस में चिंता भी जताई। यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, यह हमें समझने की जरूरत है।

महोदय, अब मैं थोड़ा समय लूँगा। वर्ष 2005-06 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ रुपये मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग के खरीदवाने के मसौदे पर हस्ताक्षर किया गया और 43 एयरक्राफ्ट, एयरबस। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपये मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) यह आप समझिए कि वर्ष 2005 के पहले... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आपने उस समय आवाज उठाई।... (व्यवधान) रिकॉर्ड पर आपका कोई स्टेटमेंट है।... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी।... (व्यवधान) मैं 8 घंटे कल सुन रहा था। कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए।

वर्ष 2005 के पहले, महोदय, देखिए जो एयर इंडिया 15 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बनाती है, जो इंडियन एयरलाइन्स 50 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बनाती है, 50 हजार-55 हजार करोड़ रुपये का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाते हैं, भाग एक 'क' और भाग 'क' की उस 111 एयरक्राफ्ट्स में से 15-20, 777-300ईआर, जो जरूरत है, उससे ज्यादा खरीदे जाते हैं और 5 एयरक्राफ्ट बी300-200ईके, यह वर्ष 2013-14 में बेचे जाते हैं। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें, 55 हजार करोड़ रुपये का जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेश्यो हो और इंडस्ट्री में लीवरेज देखा जाता है, एक सीमा से ज्यादा किसी कंपनी में नहीं लिया जाता है, नहीं तो कंपनी डूबेगी।

(1335/KN/VR)

जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1 है। उसमें आप 55 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेते हो और आप दोनों कम्पनीज़ का मर्जर करते हो। दोनों कम्पनियों का कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग और उनके एम्प्लॉइज का रिटेंशन प्रोग्राम अलग है, उन दोनों कम्पनीज को आप मर्ज करते हो, तो जो दो कम्पनीज़ वर्ष 2005 में प्रॉफिट मेकिंग कम्पनीज़ थीं, जिस साल मर्जर किया गया, उस साल से 3300 करोड़ रुपये का लॉस बनाने की शुरुआत की गई। वर्ष 2007-08 से... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दा ने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए।... (व्यवधान) वर्ष 2007-08 से 2020-21 तक हर साल 3 हजार से साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का लॉस और 85 हजार करोड़ रुपये का एयर इंडिया का कम्बाइंड लॉस हुआ। The result of acquisition of 111 aircraft; sale of five B-300 200EK aircraft; buying of 15 B-777 300ER aircraft; merger of two companies with totally two different cultures, two different visions, two different employees retention programmes is a loss of Rs.20 crore per day. साढ़े सात हजार करोड़ का लॉस... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसके आगे सुनिए। इसके साथ-साथ जो लिबरलाइजेशन किया गया... (व्यवधान) आपने पूछा है, तो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं तो मैं चुप था। आपने ही पूछा है और आपने ही मेरा मुंह खुलवाया है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। आपने ही मेरा मुंह खुलवाया है। मैं तो बैठ गया था।... (व्यवधान) इसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ बायलेटरल्स... (व्यवधान) आप सुनिए, वर्ष 2004-05 में बायलेटरल की लिबरलाइजेशन की गई। भारत के जो कैरियर्स थे, 51 मिलियन की बायलेटरल्स थीं, उनको बढ़ा कर 51 मिलियन बायलेटरल्स मतलब जितनी क्षमता सीट्स की विदेशी एयरलाइंस को यहां आने के लिए और हमारी एयरलाइंस को वहां जाने के लिए दी जाती है, उसको बढ़ा कर 180 मिलियन किया गया।... (व्यवधान) खाड़ी देशों में 100 से 200 प्रतिशत बढ़ाया गया, साउथ ईस्ट नेशंस को 200 प्रतिशत बढ़ाया गया और यूरोपियन नेशंस को 400 प्रतिशत बढ़ाया गया।... (व्यवधान) जबकि भारत के कैरियर के पास वह क्षमता नहीं थी। इसके आधार पर एयरलाइंस की क्या पोजीशन हुई? जब यह स्थिति हुई, जो मुझसे दादा पूछ रहे थे... (व्यवधान) 14 साल के लॉसेस 85 हजार करोड़ रुपये, भारत सरकार की इक्विटी इनफ्यूजन 54 हजार करोड़ रुपये, गवर्नमेंट ग्रांट्स 50 हजार करोड़ रुपये, 190 हजार करोड़ तो यह हो गया और वर्तमान का नेट डेट 66 हजार करोड़ रुपये था तो 2 लाख 50 हजार करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई थी। यह पैसा भारत सरकार का नहीं है। यह पैसा भारत की 135 करोड़ जनता का है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया, हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा ताकि भारत सरकार और भारत की जनता के पैसे का संरक्षण किया जाए।... (व्यवधान) उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन मिशन के लिए और आम जन के लिए उसका सदुपयोग किया जाए, इसलिए इस कम्पनी का विनिवेश किया गया।

प्रेमचन्द्रन जी और दादा ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति क्या है? हमारे शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट में विस्तृत रूप से पहली कंडीशन यह लिखी गई है कि एक साल के लिए कोई भी कर्मचारी को फायर नहीं किया जाएगा।

(1340/GG/SAN)

उनको एक साल के लिए रीटेन किया जाएगा। एक साल के बाद अगर किसी को रिटेंशन से हमें हटाना है तो केवल वीआरएस स्कीम के आधार पर किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। जहां तक मेडिकल की बात प्रेमचंद्रन जी ने कही, रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्पलॉइज़ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो भारत सरकार का व्यय होता था, वही सीजीएचएस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर किया जाएगा।। यह हम लोगों का संकल्प है। इसी के साथ हमारी विचारधारा है कि कर्मचारियों में सुरक्षा भी उत्पन्न हो ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को और इस एयरलाइन को भी दोबारा स्थापित किया जाए तथा भारत सरकार और भारत की जनता के पैसे और उनकी आमदनी की रक्षा की जाए। … (व्यवधान) सुदीप दा, कोलकाता एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि द्वितीय एयरपोर्ट एक अलग मुद्दा है। कोलकाता एयरपोर्ट में भी हम लोग विस्तारीकरण कर रहे हैं। हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। नयी टर्मिनल बिल्डिंग बनायी जा रही है, सब कुछ बनाया जा रहा है। … (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में हम बहुत एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। उसके लिए कृपा कर के आप मुझे मदद करें। जहां हमको जमीन मिलेगी, वहां हम लोग जरूर करेंगे, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री हनुमान बेनिवाल एवं श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। ”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1343 बजे

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल ।

… (व्यवधान)

1343 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्रीमती सोनिया गांधी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए, आपको मौका दिया जाएगा। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए, आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। Please let the House be in order.

… (व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली): सभापित महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक ज़रूरी मामले पर बोलना चाहती हूँ जो हमारे देश के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश की सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं।

(1345/RV/SNT)

जब स्कूल बंद हुए थे, तब मिड-डे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी। यह तो राष्ट्रीय फुड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया। लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं है। यह सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका को बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसा संकट, जिसका सामना बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे-जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड-डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने में भी मदद मिलेगी, जो इस महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं।

सभापति जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में पाँच वर्ष से कम आयु के वे बच्चे, जो बेहद कमजोर हैं, उनका प्रतिशत वर्ष 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए।

---

* Please see pp. 356 for the list of Members who have associated.

सभापति जी, इसीलिए, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत गर्म और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए और मिड-डे मील को भी तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाने चाहिए। साथ ही, आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्म, पका हुआ भोजन तीन साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए कम्युनिटी किचन शुरू करने का प्रावधान करना चाहिए।

सभापति जी, मैं उम्मीद करती हूं कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। धन्यवाद।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सभापति जी, 21 तारीख को बंगाल में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना घटी।... (व्यवधान) उस दिन से कुछ दिन पहले टी.एम.सी. के एक डिप्टी पंचायत प्रधान का मर्डर हो गया था। उसका बदला लेने के लिए पाँच घरों को जला दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उस जलते हुए घर से बाहर न आ पाएं, इसलिए बाहर से घर के दरवाजे को ताला-चाभी से बंद कर दिया गया।... (व्यवधान) उन 10-12 लोगों में बच्चे भी थे और सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलौंग करते हैं। सबको जलाकर राख कर दिया गया और पूरी मानवता वहां रोती रही।... (व्यवधान) सिर्फ यही नहीं, वहां के गांव वाले बोल रहे हैं कि 20 लोग लापता हैं।... (व्यवधान) पुलिस के सामने यह कांड किया गया।... (व्यवधान)

सर, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि अगर इन 13 लोगों की मौत को इसमें जोड़ लें तो पिछले एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल में 26 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हमारे सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी के ऊपर बम से हमला किया गया। 2 मई के बाद से वहां के विरोधियों के ऊपर कंटीन्यू पोस्ट-पॉल वॉयलेंस चल रहा है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय हस्तक्षेप हो और केन्द्र सरकार को जो अधिकार संविधान में दिया गया है, उस अधिकार का केन्द्र सरकार प्रयोग करके हमारे संविधान में जो उपयुक्त धारा दी गई है, उस धारा का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री एम. गुरुमूर्ति - उपस्थित नहीं।

... (<u>व्यवधान</u>)

(1350/SRG/MY)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): The prices of LPG cylinders have increased in the last few months. ... (*Interruptions*). Currently, LPG cylinders, both subsidised and non-subsidised, are available for around Rs. 900 as on 1st March, 2022 in major metros. ... (*Interruptions*). Such high cost of domestic LPG cylinders has badly affected poor and middleclass households. ... (*Interruptions*). The prices have increased by 50 per cent and prices will further increase with rising international oil and gas prices due to the ongoing Ukraine-Russia conflict. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आपकी बात रखी जा चुकी है। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात रख चुके हैं। आपको पूरा अवसर दिया गया है। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): It has been seen that the LPG subsidy is not provided nowadays for majority of domestic users and even if it is provided, the amount is too less. … (*Interruptions*). There is also a need to link the subsidy provided as per percentage of the price of the LPG cylinder, so that as price increases, the subsidy provided also increases. The increasing price of LPG cylinders is affecting household finances much more as we come out of COVID-19, and when inflation is showing an upward trend. … (*Interruptions*). Thus, I request, through you, to the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas to take these suggestions into consideration and provide LPG cylinders at subsidized rates for domestic users according to the inflation.

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, artefacts of rich heritage and culture of old civilization were discovered in Keezhadi, Tamil Nadu. Similar Tamil, Sind and associated civilizations artefacts were discovered in Krishnagiri district. … (*Interruptions*)

It has been registered in history books of the pre-British, British and post-British era. Pre-historic rock paintings, cave paintings are found enormously in Krishnagiri district of Tamil Nadu. … (*Interruptions*). The exact date of the painting has not been ascertained, but as per the Archaeological Department of Tamil Nadu, it may belong to the Neolithic period around 5000 BC to 10000 BC. … (*Interruptions*). This is one of the earliest murals of Tamil Nadu. Many Archaeologists have found Megalithic culture in many places in the Krishnagiri region. … (*Interruptions*). Different types of burials were noticed like cairn-circle with sarcophagus, cairn- circle with cist, dolmens. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Myladumparai, Mallasamudram, Thalapalli, Maharaja Kadai, Mallappadi, Aandimalai, Bayanapalli, Krishnadevaraya Hillock, Syed Basha Hillock are some of the important places. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप इनको बैठाइए।

… (<u>व्यवधान</u>)

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Several early rock paintings and epigraphy have been destroyed by indiscriminate quarrying. … (*Interruptions*) I urge upon the Government, through you, to declare the area as a Centrally-protected area and explore the history through ASI. … (*Interruptions*)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): आप एक मिनट के लिए रूकिए। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ।… (व्यवधान).

Sir, in Birbhum district, one murder took place and the name of the person who was killed was Bhadu Sheikh. He was the Deputy Chairman of a municipality town and he belongs to our Party. He was killed and murdered. … (*Interruptions*). He was an *Up-Pradhan*. This is not a fight between two political parties. It is not that our fight is with BJP or our fight is with Congress or CPM. It was an internal fight amongst the families itself. … (*Interruptions*). The matter has been reviewed by the hon. Chief Minister with high level officials. … (*Interruptions*). 20 persons have been arrested till now. … (*Interruptions*). I have asked for an appointment with Amit Shah Ji also. … (*Interruptions*). We want to meet him. We will tell him in detail. … (*Interruptions*). It is expected that anytime we may be called for. … (*Interruptions*). I will say that let the culprits be arrested. … (*Interruptions*). All punishments be given. … (*Interruptions*). The Chief Minister has fully assured … (*Interruptions*). It is not a political fight between any two political parties … (*Interruptions*). आप सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि इसको लेकर आप राजनीति मत कीजिए।

(1355/AK/CP)

*SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. In my Dindigul parliamentary constituency, around the surrounding areas of Natham, mango is cultivated in large scale. I request the Union Government to set up a factory for producing mango juice in order to improve the livelihood of farmers of this area. In Nilakkottai area of my constituency, fragrant flowers are cultivated in large scale by the farmers. I urge upon the Union Minister to take necessary steps to help in export of fragrant flowers produced from this area. Dindigul Municipal Corporation has been declared as smart city. But it remains as a mere announcement. I urge upon the Hon. Minister to implement the schemes relating to smart city in Dindigul. Dindigul district is fully dependant on agriculture. Keeping in view the future of the youth of this district and to create employment opportunities for them, I request the Hon. Railway Minister to set up a factory to manufacture railway equipments in Dindigul. The subway at Aranmanai Pudur between Dindigul and Pollachi remains in a pathetic condition where it cannot be utilitized during rainy season. I urge upon the Union Minister for Railways to convert this Railway Gate (across L.C. No. 25) once again as a manually operated Level Crossing so that this road can be utilized by the people of this area during rainy season. Thank you.

#SHRIMATI SATABDI ROY (BANERJEE) (BIRBHUM): Respected Sir, I would like to raise certain issues regarding MGNREGA in my Birbhum constituency. About 50 odd staffs are not getting any salary for the last 2 months and not only in Birbhum, but this number is very high in other parts of West Bengal as well. Even those who have received salary, their P-tax and EPF have not been deposited so far. Secondly, the unskilled labourer, belonging to the general category who do hundred days work are also not getting their wages for last 6 months. So they will be compelled to stop work, there is no other option. There are about 4.5 lakh job card holders in Birbhum who are working, but out of the 1.5 crore man-days earmarked in the budget, not more than 33.33 days of work are being allocated per family.

---

* Original in Tamil

Original in Bengali

Though there is a demand of 50 days of work on an average in the district. Sir, we come to Parliament as the representatives of the common people who come to us with their demands and aspirations. They hope that we will solve all their problems. Thus my request to Honourable Minister is that these problems may be solved as early as possible.

If the issues are addressed, then the difficulties of the people of West Bengal, particularly those of my Birbhum constituency may be done away with. And it may also help the representatives like us to redress their grievances easily and effectively. Thank you Sir.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप अपनी बात कह चुके हैं। Now please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rodmal Nagar -- not present.

… (*Interruptions*)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, human animal conflict is the main issue being faced in Kerala. … (*Interruptions*) Sir, let the House be in order. … (*Interruptions*)

Human animal conflict is the main issue being faced in Kerala. … (*Interruptions*) In my Constituency more than 350 kms. of border is being shared with forest land. … (*Interruptions*) As per the Kerala Government's latest statistics more than 1,233 people have lost their lives in the last 10 years and more than 6,803 people have been injured. … (*Interruptions*) In my Constituency alone 40 people have lost their lives in recent years. … (*Interruptions*) The death compensation due is Rs. 101 crore. … (*Interruptions*) A total of 34,875 animal attacks had taken place. … (*Interruptions*) This data has been officially published by the Government. … (*Interruptions*) So, our farmers are facing a serious situation. … (*Interruptions*)

I believe that precautionary measures should be taken to prevent this for which enough funds are required. … (*Interruptions*) So, I am demanding special allocation for Kerala to take-up the work of precautionary measures like crash guard fencing, rail fencing, etc. … (*Interruptions*)